Modi Govt's transparent mining policy yielding results: Sai

■ Staff Reporter

NARENDRA Modi Government has introduced auction system for mines and ended the era of corruption, favouritism and nepotism in mining and more scientific, eco-friendly mining can boost the national economy, improve the growth trajectory and bring prosperity, said Union Minister of State for Steel and Mines Vishnu Deo Sai.

Speaking to select group of reporters on Sunday during his visit to city, Sai stated initiatives like District Mineral Foundation, a representative body at district-level can undertake developmental works in mine infested areas through Prime Minister Khanij Kshetra Kalyan Yojana. Presently Rs 550 crore have been collected by DMFs and if the mining activity achieves its full potential a sum of Rs 6,000 crore every year can be generated, he stated. This fund can redress grievances of project affected persons-mostly tribal-and used for their progress.

Union Minister of State for Steel and Mines Vishnu Deo Sai interacting with mediapersons while top officials of PSUs look on.

Mines Minister also stated that MECL has been appointed as nodal agency of National Mineral

(Contd on page 2)

Modi Govt's transparent mining...

Exploration Trust set up pursuant to amendment in MMDR Act and a corpus of Rs 200 crore has been created. He also urged State Governments to start using provisions of amended MMDR Act pertaining to curbing illegal mining to set deterrent examples. The Centre has initiated an ambitious project with the help of Bhaskaracharya Institute for Space Aspplications and Geo Informatics and National remote Sensing Centre to super impose mining GPS enabled boundaries of mining leases on digitized cadastral maps to undertake periodic monitoring using satellite imagery.

Sai highlighted another major initiative of digitizing 6,000 exploration reports of GSI and putting it in public domain to facilitate exploration by the private sector using digitized geological reports. The Union MoS for Steel and Mines stated that mining sector has potential to boost GDP growth and mineral exploration initiatives can be owned by state governments as more exploration can lead to more mining, which can result in employment generation and economic growth. Ministry of Mines has signed MOU with ISRO for use of space technologies in mining sector and states must take advantage of this opportunity, he stated.

The States must make efforts to ensure that mining leases granted before MMDR Amendment, get Forest and Environment clearances by January 2017 deadline to prevent lapsing of leases, he stated. He informed that National Mineral Exploration Policy is likely to be notified in next couple of months. He shared details of initiatives taken by the Central Government to facilitate exploration and mining in the country.

About crisis faced by steel industry, the Union MoS for Steel stated that Government had imposed anti-dumping duty to prevent influx of cheap steel from China. However, due to global slump, the sector is passing through a rough phase, he stated while listing several initiatives to provide respite to steel sector.

CMD of MOIL G P Kundargi, CMD and MECL Dr Gopal Dhawan, IBM Controller General R K Sinha and top officials of MOIL, MECL, IBM and GSI were present.

दैनिक भास्कर, महानगर

नई नीलामी प्रणाली से दूर होगा खदानों का भ्रष्टाचार

▪ केंद्रीय इस्पात व खनिज राज्यमंत्री साई का दावा

शहर प्रतिनिधि | नागपुर. केंद्र सरकार ने खनिज खनन के लिए नई नीलामी प्रणाली लायी है। केंद्रीय इस्पात व खनन मामलों के राज्यमंत्री विष्णु देव साई ने कहा है कि नई प्रणाली से खनन मामलों में भ्रष्टाचार दूर होगा। पक्षपात व भाई भतीजावाद की शिकायतें कम होगी। खनन मामले में वैज्ञानिकता व,इको-फ्रेंडली माइनिंग को गति मिलेगी। देश में आर्थिक विकास होगा।

एक कार्यक्रम के सिलसिले में यहां आए श्री साई ने रविवार को पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में विविध सुधार कार्य किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन किया गया है। इससे खनन क्षेत्र के प्रभावित लोगों के पुनर्वसन के अलावा अन्य सहायक कार्यों में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का प्रभावी लाभ मिलेगा। जिला फाउंडेशन के माध्यम से फिलहाल 550 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। योजना का सही मायने में अमल होने पर प्रतिवर्ष 6000 करोड़ रुपये जमा होंगे। इस निधि से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में खनन प्रभावितों को लाभ मिलेगा। एमइसीएल को राष्ट्रीय खनिज खनन ट्रस्ट का नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। एमएमडीआर एक्ट में संशोधन की तैयारी है। 200 करोड़ के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। अवैध खदानों पर नियंत्रण का ठोस प्रयास किया जा रहा है। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट की सहायता से एक परियोजना पर अमल होगा। अंतरिक्ष संदेशों व सूचनाओं को त्वरित पाने में सहायता मिलेगी। खदानों के डिजीटाइजेशन का कार्य भी केंद्र सरकार करेगी। केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि 6000 खदानों के डिजीटाइजेशन के संबंध में रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। खनिज मंत्रालय ने इसरो के साथ एमओयू किया है। इससे अंतरिक्ष तकनीकी व माइनिंग सेक्टर में विकासात्मक लाभ मिलेगा। एमएमडीआर संशोधन से पहले राज्य सरकार माइनिंग लीज तय कर सकती है। इसके लिए वन व पर्यावरण विभाग की अनुमति 2017 तक देने की 'डेडलाइन' दी गई है। इससे लीज संरक्षण मिलेगा। लीज लैप्स नहीं हो पाएगी। चर्चा के दौरान मायल के सीएमडी जीपी कुंदरगी, एमईसीएल के सीएमडी डॉ.गोपाल धवन, आईबीएम कंट्रोलर जनरल आर.के सिन्हा व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

नवभारत, नागपुर, 30/05/2016 पेज (7)

उद्योगों को बढ़ावा देना ही IBM का उद्देश्य

खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला का मंत्री साय ने किया उद्घाटन

व्यापार संवाददाता

नागपुर. खान मंत्रालय के इस्पात और खान राज्य मंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आईबीएम का कार्य देश के विविध उद्योगों को बढ़ावा देने का है. देश के विकास में आईबीएम का महत्वपूर्ण योगदान है. साय एमआईडीसी हिंगना रोड आईसी चौक के समीप स्थित भारतीय खान ब्यूरो के खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला एवं प्रायोगिक संयंत्र के उद्घाटन अवसर पर संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स के महानियंत्रक आर.के. सिन्हा, भारतीय खान ब्यूरो की इंदिरा रवींद्रन, मायल के सीएमडी जी.पी. कुंदरगी, एमईसीएल के सीएमडी डा. गोपाल धवन, डा. डी.आर. कानूनगो, एस.आर. भगत व अन्य उपस्थित थे.

देश के लिए गौरव की बात

उन्होंने कहा कि खनिज में से धातु, मिनरल, रसायन का अनुसंधान करना व उसका विश्लेषण करने का महत्वपूर्ण कार्य इस प्रयोगशाला में किया जाता है. इसके चलते देश के विकास में भी यह संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. आईबीएम जिस तरह देश व समाजहित के कार्य कर रही है, वह गौरवपूर्ण है. उन्होंने खान मंत्रालय के बारे में कहा कि पिछले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की घोषणा के उपरांत, उक्त विषय पर पहले खान मंत्रालय द्वारा नियम बनाए गए तथा अधिकांश प्रमुख खनिज समृद्ध राज्यों ने उन नियमों को अपना लिया है. इसके अतिरिक्त इन राज्यों द्वारा जिला स्तर पर जिला खनिज कोषों की स्थापना की जा रही है. 12 राज्यों में से 8 राज्यों में नियम बन चुके हैं. और जिला स्तर पर डीएमएफ की स्थापना हो चुकी है. डीएमएफ द्वारा लगभग 550 करोड़ रुपये एकत्र हो चुके हैं.

उन्होंने कहा कि संशोधित एमएमडीआर एक्ट, 2015 के अनुसार प्रमुख खनिजों के सभी खनन पट्टों को निजी पक्षों को नीलामी के द्वारा आवंटित किया जाना है. तद्नुसार 3 राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओड़िशा में प्रमुख खनिजों के 6 ब्लाकों अर्थात लाइनस्टोन, सोना, लौह-अयस्क की नीलामी सफलतापूर्वक हो चुकी है. गैर कोयला खानों के मामले में भारत में पहली बार यह कदम उठाया गया है.

45 ब्लाकों की करेंगे नीलामी

2016-17 में अपेक्षा है कि अन्य 45 ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी और इसके अतिरिक्त 17 ब्लॉकों की, जहां राज्य बोलीकर्ताओं से पर्याप्त उत्तर नहीं प्राप्त कर सके थे, में भी दोबार नीलामी की जाएगी. खनन पट्टे के आवंटन को सरल एवं कारगर बनाने के लिए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 अधिसूचित किया गया है. वहीं केंद्रीय बजट 2015-16 में फ्लैट और नॉन फ्लैट दोनों इस्पात पर बेसिक सीमा शुल्क की उच्चतम दर 10 प्रश से बढ़ाकर 15 प्रश की गई है.

ली विविध जानकारी

माइक्रोस्कोप से खनिज के विविध धातू व मिनरल का अनुसंधान की जानकारी अनुसंधानकर्ताओं से ली और खनिज के धातु और मिनरल के अनुसंधान के लिए आधुनिक एक्स-रे मशीन के उपयोग के बारे में इंदिरा रवींद्रन ने बताया. कार्यक्रम का संचालन डा.संध्या लाल ने किया.

विष्णुदेव साय यांचे प्रतिपादन : मंत्रालयांतर्गत विभागांचा आढावा

खासगी क्षेत्राला उत्खननाचा परवाना देणार

नागपूर : गेल्या वर्षी अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात फारसे उत्खनन झाले नाही. यंदा मोदी सरकारने भूगर्भातील खनिजांच्या उत्खननावर भर दिला असून, यासाठी खासगी भागीदारांना परवाना देण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय खाण व पोलाद मंत्री विष्णुदेव साय यांनी रविवारी येथे दिली.

मोदी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त त्यांनी मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या विभागाच्या कामगिरीचा मॉयलच्या सभागृहात आढावा घेतला आणि पत्रकारांशी संवाद साधला. साय यांनी विभागांतर्गत एमईसीएल, आयबीएम, जीएसआय, मॉयल आदी विभागाची वर्षभरातील कामगिरीची माहिती घेतली.

खाण आणि खनिज अधिनियमात संशोधन

केंद्राच्या उपलब्धीची माहिती देताना साय म्हणाले, उत्खनन क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी खाण आणि खनिज अधिनियमात संशोधन केले आहे. संशोधित एमएमडीआर कायदा-२०१५ नुसार प्रमुख खनिजांच्या सर्व उत्खनन पट्ट्यांना खासगी क्षेत्राला लिलावाद्वारे देण्यात येणार आहे. त्यानुसार छत्तीसगड, झारखंड आणि ओडिशा या तीन राज्यांमध्ये प्रमुख खनिजांच्या सहा ब्लॉकचा लिलाव केला आहे. आर्थिक वर्षात अन्य ४५ ब्लॉकचा लिलाव करण्यात येणार आहे. याशिवाय अतिरिक्त १७ ब्लॉकचा दुसऱ्यांदा लिलाव होईल. सरकारने राष्ट्रीय उत्खनन खाण ट्रस्ट स्थापन करून रॉयल्टीद्वारे मिळणारी रक्कम विकासावर खर्च करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून एमईसीएलला नियुक्त केले असून २०० कोटी देण्यात आल्याचे साय म्हणाले.

आदिवासींचे पुनर्वसन

खनिज जंगलात असतात. आदिवासींच्या पुनर्वसनासाठी पंतप्रधान खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तयार केली आहे. त्यासाठी तयार केलेल्या नियमांचा अधिकांश प्रमुख खनिज समृद्ध राज्यांनी अवलंब केला आहे. या राज्यांद्वारे जिल्हास्तरावर जिल्हा खनिज कोष स्थापन करण्यात येत आहे. १२ राज्यांपैकी ८ राज्यांमध्ये नियम बनले आहेत. जिल्हास्तरावर डीएमएफची स्थापना केली आहे. डीएमएफद्वारे जवळपास ५५० कोटी रुपये एकत्र झाले आहेत. याशिवाय संपूर्ण देशात अवैध उत्खननावर नियंत्रणासाठी खाण मंत्रालयाने दोन संस्थांच्या सहकार्याने जीपीएस आधारित एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केली आहे. देशात अवैध उत्खननावर नियंत्रणाच्या दिशेने सरकारचे महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे साय यांनी सांगितले.

पोलाद उद्योगात मंदी

आंतरराष्ट्रीयस्तरावर पोलाद उद्योगात मंदीचे वातावरण आहे. या उद्योगाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने आयातीवर पाच वर्षे ॲन्टी डम्पिंग ड्युटी लावली आहे. देशात २०२५ पर्यंत पोलादाचे ३०० दशलक्ष टन उत्पादन करण्याचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी आर ॲण्ड डी तसेच खासगी क्षेत्रातील उद्योजकांचे सहकार्य घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विदर्भासाठी विशेष योजना नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सेल तोट्यात आहे. त्यातून लवकरच बाहेर येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

याप्रसंगी मॉयलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक जी.पी. कुंदरगी, एमईसीएलचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक गोपाल धवन, आयबीएमचे मुख्य महाव्यस्थापक रंजन के. सिन्हा, जीएसआयचे डीडीजी एन. कुटुंब राव, मॉयलचे व्यवस्थापकीय संचालक (तांत्रिक) दीपांकर सोम, वित्त संचालक एम. चौधरी आणि सर्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

खाण विस्थापितांसाठी अनेक योजना : विष्णुदेव साय

नागपूर, ता. २९ : खाण विस्थापितांच्या विकासासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध असून गेल्या दोन वर्षांत अनेक विकास योजना सुरू केल्याची माहिती केंद्रीय पोलाद व खाण राज्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनी पत्रकारांशी वार्तालाप करताना दिली.

विदर्भातील खाण क्षेत्राचा आढावा घेण्यासाठा साय यांनी आज नागपूरला भेट दिली. यानंतर काही निवडक पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, गेल्या दोन वर्षांत खाण विस्थापितांच्या विकासासाठी अनेक पावले उचलली

विष्णुदेव साय

गेली. नॅशनल एक्सप्लोरेशन माईन्स ट्रस्ट (एनईएमटी) स्थापन करण्यात आला. या ट्रस्टच्या माध्यमातून खाण विस्थापितांच्या विकासासाठी योजना राबविल्या जाणार आहेत. या ट्रस्टची नोडल एजन्सी म्हणून एमईसीएल काम पाहणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने २०० कोटी रुपये ट्रस्टला दिले आहेत. याशिवाय खासगी खाण मालकही या ट्रस्टमध्ये सामाजिक बांधीलकी म्हणून मदत करणार आहेत. याशिवाय खाणी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना राबविली जाणार आहे. या जिल्ह्यांमध्ये एक प्रतिष्ठान स्थापन केले जाईल. या प्रतिष्ठानला खाणीच्या स्वामित्व शुल्कातून मिळणाऱ्या रकमेपैकी ३० टक्के रक्कम या प्रतिष्ठानला दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खाण उत्खननासाठी सहा हजार प्रस्ताव केंद्राला मिळाल्याचे सांगून ते म्हणाले, आतापर्यंत सहा खाणींचा लिलाव झाला. खाण उत्खननाची परवानगी देताना पारदर्शकता पाळली जाणार असून सर्व व्यवहार लिलाव पद्धतीने होणार आहेत. उर्वरित खाणींचे लिलाव लवकरच करण्यात करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलाद निर्मिती क्षेत्रात सर्व जगातच मंदी आहे. तरी आज भारत पोलाद निर्मितीत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताला दुसऱ्या क्रमांकावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी अँन्टी डम्पिंगसारख्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.